आकाशवाणी
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 15.05.2026 समय 1830

मुख्य समाचार :–

- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट–यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया।
- राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में 'स्वामी विवेकानंद उत्तराखण्ड ई–पुस्तकालय योजना' लागू। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है उद्देश्य।
- पिथौरागढ़ जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए "हेलो हेल्प" सेवा शुरू।
- ऊधमसिंहनगर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, रुद्रपुर में "सुरक्षित ईंधन, सुरक्षित जीवन" अभियान का शुभारम्भ।

....

नीट–यूजी 2026 परीक्षा

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी– एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट–यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट–यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।

ई–पुस्तकालय योजना

उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में 'स्वामी विवेकानंद उत्तराखण्ड ई–पुस्तकालय योजना' लागू कर दी गई है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाइन एकीकृत प्लेटफार्म पर सभी पाठ्यक्रमों की ई–बुक सहित अन्य डिजिटल साम्रगी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि छात्र–छात्राओं को किताबों को लेकर कोई दिक्कत न हो। योजना के ठोस क्रियान्वयन के लिये शासन स्तर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि 'स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई–पुस्तकालय योजन' के तहत अध्ययनरत छात्र–छात्राओं और शिक्षकों को एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफार्म पर पाठ्य–पुस्तकें, उत्कृष्ट लेखकों की किताबें, शोध पत्र और अन्य डिजिटल साम्रगी एक क्लिक पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई–पुस्तकालय का उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है, ताकि आर्थिक और भौगोलिक कारणों से कोई भी छात्र किताबों से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि ई–लाइब्रेरी योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान रूप से मिल

सकेगा और छात्र अपनी सुविधानुसार आसानी से विषयवार पुस्तकों की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा इस योजना का लाभ तकनीकी शिक्षा, आयुष व चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभाग, निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी ले सकेंगे। इसके लिये उन्हें निर्धारित शुःल्क देना होगा।

पौड़ी प्रगति पोर्टल

पौड़ी जिले में विकास कार्यों को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए "पौड़ी प्रगति पोर्टल" लॉन्च किया गया है। यह अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि पोर्टल के जरिए सभी विभागों की प्रगति पर निरंतर नजर रखी जा सकेगी, जिससे कार्यों में गति के साथ–साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर सतत निगरानी रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हेल्पलाइन सेवा

पिथौरागढ़ जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए "हेलो हेल्प" सेवा आज से शुरू हो गई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 94–58–14–46–51 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। जिलाधिकारी आशीष भटगाईं ने आज हेल्प डेस्क कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी दूरस्थ क्षेत्र से नागरिक अब हिंदी या स्थानीय भाषा में अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकेंगे। हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों तक तुरंत भेजा जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनता और शासन के बीच संवाद को मजबूत बनाना है।

सुरक्षित ईंधन अभियान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर की ओर से आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, रुद्रपुर में "सुरक्षित ईंधन, सुरक्षित जीवन" अभियान का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को ईंधन की बचत के लिए प्रेरित करते हुए सप्ताह में दो दिन पैदल या साइकिल से न्यायालय परिसर आने का आह्वान किया गया।

अभियान को व्यावहारिक रूप से अपनाते हुए प्राधिकरण की सचिव ममता पंत अपने निवास से लगभग पैदल चलकर न्यायालय परिसर पहुंचीं। उन्होंने कहा कि एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य आमजन में ईंधन व पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

प्रशिक्षण शिाविर

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में इन दिनों महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बारह दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को अगरबत्ती, धूप और पारंपरिक दिए बनाने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। प्रतिभागियों को केवल अगरबत्ती और धूप बनाना ही नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से मिलने वाली जड़ी–बूटियों के उपयोग की जानकारी भी दी जा रही है। संस्थान के निदेशक सुखविंदर कादयान ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए स्वरोजगार ही सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि कम पूंजी लगाकर आसानी से काम शुरू किया जा सके।

वहीं, प्रशिक्षणार्थी जानकी जोशी ने बताया कि प्रशिक्षण से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वे भविष्य में स्वरोजगार शुरू करने की योजना बना रही हैं।